साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

भोपाल, सोमवार 14-20 मार्च 2022, वर्ष-7, अंक-50

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

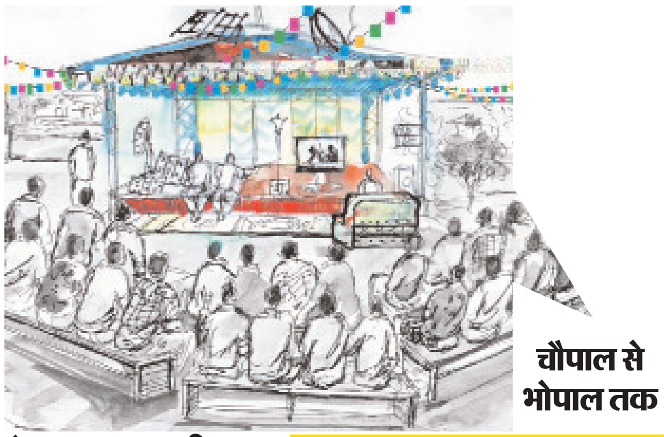

चौपाल से भोपाल तक

मध्यप्रदेश बजट-2022-23 में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश

शिवराज के वित्त मंत्री ने किसानों के लिए खोला पिटारा

प्रशासनिक संवाददाता। भोपाल

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई ह। बजट भाषण में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने जॉब-इंडस्ट्री, खेती-किसानी, एजुकेशन समेत कई मुद्दों पर बात कही। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 60 साल से ज्यादा के लोगों को तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। मध्यप्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच पेश हुए बजट के सबसे खास बात ये रही कि इसे अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों और केवल अर्थशास्त्रियों ने नहीं बनाया। इस बजट के लिए शिवराज सरकार ने जनता से सुझाव मांगे थे। उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है।

पशुपालनः मध्यप्रदेश में घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा देंगे

बजट विशेष पेज 04-05 पर पढ़ें

किसानों को मिला बहुत कुछ

- कृषि निर्यात योजना के साथ ही एक उत्पाद एक जिले के लिए काम होगा
- सरकार उद्यानकी फसलों की भंडारड़ क्षमता बढ़ाएगी
- 18650 करोड़ की नई माइक्रो सिंचाई योजना शुरू होगी
- मुख्यमंत्री मत्स पालन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा
- मुख्यमंत्री पशुपालन योजना की शुरुआत होगी
- बिजली बिल पर 25000 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
- जैविक खेती के लिए 1,001 करोड़ रुपए बैंक निवेश होगा
- दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया
- पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
- भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़, छतरपुर का राजगढ़ पैलेस निजी हाथों में जाएगा
- स्वरोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा
- स्वसहायता समूहों को 1,100 करोड़, यह 2021-22 के मुकाबले 100 फीसदी ज्यादा
- बिजली: अब सागर, छतरपुर और ओंकारेश्वर में लगेंगे सोलर प्लांट
- मध्यप्रदेश में गायों की सेवा के लिए नई योजना

सिंगल क्लिक से कैसी राहतः एक माह बाद भी लाखों किसानों के खाते में नहीं आई 'फूटी कौड़ी'

प्रदेश के 36 जिलों में किसानों को नहीं मिला फसल बीमा का पैसा!

संवाददाता। भोपाल

फसल बीमा। एक क्लिक यानी बटन दबाते ही 49 लाख किसानों के खाते में 7600 करोड़ रुपए ट्रांसफर। यही दावा था सोशल मीडिया पर। 12 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में बटन दबाया भी, लेकिन हकीकत यह है कि एक महीने के बाद भी लाखों किसानों के खाते खाली हैं। किसान चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी बात यह कि कृषि के अफसर और बैंक वाले खुद भी कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि किस किसान को कितने पैसे मिले, इसकी कोई सूची जिलों में नहीं है। प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे कि तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ किसानों का पैसा रुका है, लेकिन जल्द मिल जाएगा। एक गोलमाल यह भी है कि किस किसान को कितने पैसे मिले यह उसे तब पता चल रहा, जब उसके पास बैंक से मैसेज आया। बीमा का लाभ वाले किसानों की सूची का गायब होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ तो गड़बड़ी है। प्रदेश के 36 जिलों में गड़बड़ियां सामने आई है। कहीं किसानों को पैसे मिले ही नहीं। कहीं मिले तो हिसाब नहीं। कहीं बताया जा रहा है कि पुराने कर्ज में एडजस्ट कर लिए गए। कहीं आधार लिंक नहीं तो कहीं संयुक्त खाते को कारण बता रहे हैं। हर जिले में अलग कहानी। लेकिन, एक बात यह कि किसान भटक रहे हैं। नाराज हैं।

अलग-अलग बीमा कंपनी

प्रदेश में चार बीमा कंपनियों ने बीमा किया। सीहोर और भोपाल का बीमा रिलायंस जनरल के पास है। सागर दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सीधी सतना, सिंगरौली का काम एचडीएफसी एग्रो और बाकी 40 जिलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने किया है।

सवा करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी

भिंड जिले के 46 गांवों में ओला-पाला पीड़ित किसानों को बांटे गए 72.43 करोड़ रुपए के मुआवजे में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि 2017 से 2020 के दौरान गांवों में ओला-पाला का नुकसान दिखाकर कागजों पर ही 15 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया। जबकि जहां नुकसान हुआ था, वहां के पीड़ित किसानों को एक रुपए भी नहीं मिला।

इनका कहना है

खाते बंद व आधार से लिंक नहीं और बैंक मर्ज होने की वजह से बीमा की राशि ट्रांसफर होने में परेशानी आ रही है। जिन खातों से राशि वापस हुई है,उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 15-20 दिनों में बचे किसानों के खातों में बीमा राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

1.29 करोड़ में से 93 लाख की वसूली हो गई है। 33 लाख सही किसानों को भुगतान हो गया है। पटवारियों के निलंबन के बाद एफआईआर की गई है। एसडीएम मेरा रिश्तेदार नहीं, बल्कि कांग्रेस नेताओं ने 10-10 लाख रुपए फर्जी लिए है। जांच जारी है, कार्रवाई करेंगे।

विश्वास सारंग, मंत्री

भिंड में साल 2017 से 2020 तक ओलावृष्टि से किसान परेशान हुए और मुआवजा किसी और को बांट दिया। सरकार बताए कि क्या दो पटवारी ही दोषी हैं। एसडीएम क्या आपका रिश्तेदार है। पटवारी, एसडीएम आंखें मूंदकर किसी के खाते में कैसे पैसे डाल सकते हैं।

डॉ. गोविंद सिंह, कांग्रेस विधायक

किसानों को इंश्योरेंस कंपनी बता पाएगी कि उनके खाते में क्लेम की राशि पहुंची या नहीं। सीएम हेल्प लाइन पर आई शिकायतों का डायरेक्टर कृषि विभाग की अध्यक्षता में बनी टीम निराकरण कर रही है। विभाग के पास कोई डाटा नहीं है।

अजीत केसरी, पीएस, कृषि विभाग, मप्र

जिलों की एक की कहानी

विदिशा: तीन हजार किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। 650 किसानों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। को-ऑपरेटिव बैंक के 2200 किसानों के खातों में आई 12.55 करोड़ की बीमा राशि वापस चली गई।

देवास: कांता बाई ने बताया कि बैंक और सोसायटी दोनों में प्रीमियम कटी, लेकिन पैसा खाते में नहीं आया।

सागर: भुंवारा के श्याम आदिवासी ने बताया कि तीन बार बैंक जा चुका हूं, हर बार पैसा नहीं आया।

बुरहानपुर: 5 हजार 470 किसानों को 5.89 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि जारी हुई है। लेकिन राशि का वितरण नहीं हो पाया है।

गुना: 80 हजार किसानों के खाते में 87.73 करोड़ डालने का दावा किया था, अधिकांश खाते में पैसा नहीं आया।

खंडवा: 25 हजार किसानों के खातों की जानकारी दोबारा से बीमा कंपनी ने मंगाई है। इनके खातों में तकनीकी त्रुटि होने से राशि नहीं आ पाई है।

प्रदेश में पहला टेक्नालॉजी पाक्र जबलपुर में तैयार किया गया

किसानों की फसल को खरपतवारों से बचाएगा टेक्नालॉजी पार्क

संवाददाता। जबलपुर

किसानों की फसल को चौपट करने वाले खरपतवारों के कंट्रोल के लिए मप्र में पहला टेक्नालॉजी पार्क जबलपुर के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के कैंपस में तैयार किया गया है। इस पार्क में किसानों को न सिर्फ उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवारों, बल्कि जल में उगने वाले जलीय खरपतवारों के बारे में जानकारी देकर यह भी बताया जाएगा कि वे इसे अपने खेतों, तालाबों पर वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग कर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।

पांच एकड़ में फैला पार्क- यह टेक्नालॉजी पार्क कैंपस के अंदर 5 एकड़ में तैयार किया गया है। इस पार्क में सीजन के मुताबिक फसलों को लगाया गया है। साथ ही उनके साथ खरपतवारों के नियंत्रण के बाद अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति के बाद क्या लाभ हैं, इसे भी डेमोस्ट्रेट किया गया है। पार्क में आने वाले किसानों को फार्म जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जैविक नियंत्रण

वैज्ञानिकों ने बताया, कि जल में होने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जैविक पद्धति से काम किया जा रहा है, ताकि जल में रहने वाले जलीय जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार को खत्म किया जा सके।

डीडीजी पहुंचे पार्क देखने

प्रदेश के पहले टेक्नालॉजी पार्क को देखने के लिए भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद (आईसीएआर) के डीडीजी डॉ. सुरेश कुमार चौधरी पहुंचे। भ्रमण के बाद उन्होंने वीड कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर किए जा रहे वैज्ञानिकों के प्रयास पर संतोष जाहिर किया।

जमीन, खेतों व जल में होने वाले खरपतवारों (वीड) के उन्मूलन को लेकर हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। किसानों के लिए इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए नई तकनीकों की जानकारी एक ही स्थान पर मिले इसके लिए अनुसंधान कैंपस में ही टेक्नालॉजी पार्क तैयार कर किसानों के लिए खोल दिया गया है। निश्चित ही किसान इन तकनीकों से वीड कंट्रोल के साथ उत्पादन बढ़ा सकेंगे।

डॉ. जेएस मिश्र, निदेशक खरपतवार, अनुसंधान निदेशालय

कुपोषण की समस्या एवं समाधान

डॉ. शालिनी चक्रवर्ती
वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान
कृषि विज्ञान केंद्र, राजगढ़, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मप्र)

देश में कुपोषण या अल्प पोषण एक गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में कुपोषण के कारण प्रति वर्ष पांच वर्ष से कम आयु के दस लाख बच्चों की मौत हो जाती है। देश के कई इलाकों में कोविड काल में श्रमिकों के पलायन तथा अनाज की उपलब्धता में कमी और रोजगार के अवसरों की कमी का असर बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण स्तर बढ़ने के रूप में सामने आ रहा है। भोजन को सही मात्रा में ग्रहण न करना, भोजन को शारीरिक अवस्था के अनुरूप ग्रहण न करना तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आदि कुपोषण के मुख्य कारण हैं। कुपोषण स्वयं में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज न हो सकें। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ हैं 'कु' यानि 'कमी' और ' पोषण' यानि 'पौष्टिक तत्वों' की।

पौष्टिक तत्व जो हमें अनेकों प्रकार के भोजन व खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की कमी को पहचान कर उसे सही समय पर पूरा करने से कुपोषण से व उससे संबंधित अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। अत: स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन संबंधित जानकारी होनी चाहिए। दैनिक आहार में दूध, फल तथा सब्जियों के अलावा दालों एवं हरी सब्जियों का समावेश अत्यंत आवश्यक है।

कुपोषण दूर करने के उपाय: कुपोषण से बचने के लिए किस महंगी टॉनिक व दवा आदि के सेवन से जरूरी हैं कि अपने रोज के कार्यों व खाने पीने की आदतों को सुधारा जायें जिससे जो भी हम ग्रहण करें उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व हमें सही मात्रा में प्राप्त हो सकें। भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए किसी विशेष खाद्य पदार्थ को पकाने और खाने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए सबसे जरूरी हैं कि जो खाना हम रोज बनाते और खाते हैं उन्हीं में कुछ ऐसे बदलाव लाए जाएं जिससे वह भोजन संतुलित बने एवं सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल सके। अनाज हमेशा से मानव भोजन का एक मुख्य अवयव रहे हैं। अनाजों का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने के लिए कुछ सरल विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे-भूनकर फुलाना, खमीरीकरण तथा अंकुरण आदि कुछ सरल विधियां हैं जो कि प्राचीन काल से घरों में प्रयुक्त हो रही हैं जिनसे अनाजों की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। गेहूं के आटे में कभी बेसन, सोयाबीन व अन्य मोटे अनाज आदि का आटा मिला कर भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे उसकी पौष्टिकता एवं स्वाद दोनों में बढ़ोतरी होगी।

भोजन पकाने का ढंग ऐसा हो कि उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व नष्ट न हो, जैसे -दाल, चावल ज्यादा रगड़ कर न धोएं क्योंकि ऐसा करने से उसमें उपस्थित घुलनशील विटामिन व खनिज पदार्थ पानी के साथ निकल जाते हैं। खाना ढक कर धीमी आंच पर पकाएं, क्योंकि कुछ पौष्टिक तत्व तेज आंच व गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काटें और काटने के बाद कभी न धोएं, क्योंकि इससे उसमें उपस्थित घुलनशील तत्व नष्ट हो जाते हैं। आंटे को जहां तक संभव हो चोकर के साथ प्रयोग करें। सलाद व फल आदि को ज्यादा देर तक काट कर खुली हवा में न छोड़े इससे उसमें उपस्थित कुछ पौष्टिक तत्वों का विघटन हो जाता है।

मौसमी फलों व सब्जियों का परीक्षण कर कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, जैम, अचार, स्क्वैश आदि बनाकर अन्य मौसम में उसके स्वाद व पौष्टिकता का लुत्फ उठाया जा सकता है। जैसे टमाटर के मौसम में सस्ते दामों पर टमाटर खरीदकर उसकी परिरक्षित चटनी, अचार, प्यूरी, केचप आदि बनाकर रखें एवं बेमौसम या जब टमाटर के दाम अधिक हों उस समय इन खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर भोजन में विभिन्नता, स्वाद एवं पौष्टिकता पाई जा सकती है। परिवार के सभी लोगों को आवश्यक फल-सब्जी मिल सके इसके लिए प्रत्येक परिवार में एक पोषण वाटिका का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि घर के आसपास खाली पड़ी जगह का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। प्रतिदिन के भोजन में हरी पश्रेदार सब्जियों का या ताजी हरी सब्जी का प्रयोग जरूर करें। ताजे फलों को भी अपने भोजन का हिस्सा बनाएं चाहे सलाद के रूप में या चाट, जूस आदि के रूप में इनका सेबन करें। हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर रखा जा सकता है। इन्हें जब प्रयोग करना हो, तो चूरे के रूप में अथवा पानी में भिगोकर रखने से पुन: हरी पश्रेदार सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं। समय-समय पर दूध व उससे बने अन्य खाद्य पदाथज़ जैसे दही, पनीर, मट्ठा, लस्सी, घी, मक्खन आदि का भी प्रयोग करें। सोयाबीन का प्रयोग कई तरीकें से किया जाता है। इससे दूध बनाकर अन्य संबंधित खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इससे स्वादिष्ट दाल एवं नमकीन,, अंकुरित दाल आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह अत्यधिक पौष्टिक एवं मूल्य में कम होता हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे तिल, राजगीर, चने, अलसी आदि के प्रयोग से विभिन्न तरीके के खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, वड़ी, लड्डू, सत्तू आदि बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। इन विधियों का प्रयोग कर हम खाद्य पदार्थों से कम दामों पर पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त कर सकते हैं तथा कुपोषण की समस्या का भी कुछ हद तक निदान हो सकता है।

सारणी-1 दैनिक आहार में भोज्य पदार्थों की प्रस्तावित मात्रा

खाद्यान्न	पुरुष वर्ग के लिये दैनिक आवश्यकता (ग्राम में)		महिला वर्ग के लिये दैनिक आवश्यकता (ग्राम में)	
	शाकाहारी	मांसाहारी	शाकाहारी	मांसाहारी
अनाज	420	420	420	420
दालें	80	65	60	50
पत्तेदार सब्जियाँ	125	125	100	100
अन्य सब्जियाँ	75	75	75	75
कंदमूल	100	100	75	75
फ्ल	100	100	75	75
दूध	300	250	300	250
अण्डे	-	60	-	60

सारिणी-2 पोषक तत्वों की कमी से होने वाली प्रमुख बीमारियाँ

पोषक तत्व	पोषक तत्वों की कमी से हाने वाली प्रमुख बीमारियाँ
विटामिन -ए	रतौंधी, केरेटोमेलेशिया
विटामिन -सी	स्कवीज़, पाचन की गड़बड़ी, मसूड़ों का ददज़
विटामिन-डी	रिकेट्स या सूखा रोग, हड्डियों का कमजोर होना
विटामिन-ई	संतानोत्पादन शक्ति में कमी, बांझपन
विटामिन-के	रक्त का जमना, हृदय का कार्य प्रभावित
कैल्शियम	हड्डियों का अपूर्ण विकास
लौहा	रक्त की कमी (एनीमिया)
आयोडीन	थायराइड ग्रंथि का कार्य प्रभावित (घेंघा रोग)

रिकॉर्ड कृषि उत्पादन और बढ़ती निर्यात मांग की संभावनाएं

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी (मप्र)

वैश्विक संकट के दौर में भारत की खेती और किसानी रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। देश के किसानों की मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन और भारत सरकार की नीतियों के चलते ऐसा हो पाना संभव हो रहा है। खाद्यानों से लेकर तिलहन, दलहन, गन्ना आदि के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होने का अनुमान है। भारत में खाद्यानों के भडांर और रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न निर्यात बढ़ाने का भी अच्छा मौका है। भारत इस अवसर का लाभ उठाकर गेहूं की अच्छी कीमतों का लाभ किसानों को दे सकती है।

वैश्विक स्तर करोना के साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्यान्न की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन दोनों देश मिलकर गेहूं आपूर्ति का लगभग एक चोथाई हिस्से का निर्यात करते हैं। लेकिन युद्ध के चलते यह देश गेहूं की वैश्विक आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनियां में गेहूं सहित अन्य कृषि उत्पादों की निर्यात मांग लगातार बढ़ रही है, जिसे भारत पूरी कर पाने में सक्षम है। भारत ने इस वर्ष फरवरी के अंत तक लगभग 66 लाख टन गेंहू का निर्यात किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है।

अनुमान के अनुसार आने वाले कुछ माहों में 70 लाख टन से अघिक गेहूं का निर्यात होने की पूरी उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में गेहूं की कीमतें दस साल के उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के गेहूं की कीमतें भी वैश्विक स्तर पर 320 डालर से बढ़कर 360 डालर प्रति टन तक पहुंच गई हैं। भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अप्रैल माह के अंत तक लगभग पूरी तरह गेहूं की नई फसल आ जाएगी। इस समय वैश्विक बाजार में गेहूं की भारी कमी देखी जा रही है। उस कमी को भारत जैसा बड़ा गेहूं उत्पादक देश पूरी करने में सक्षम हैं। ऐसे में भारतीय गेहूं निर्यातकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। निश्चित रूप से गेहूं की इस वैश्विक मांग का लाभ देश के किसानों को भी मिलेगा। सरसों की तरह ही गेहूं की कीमतें भी खुले बाजार में एमएसपी से ज्यादा मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। भारत के पास गेहूं का विशाल भंडार मौजूद होने के कारण इस निर्यात मांग को पूरा करने में कोई अड़चन भी नहीं दिखाई देती है। वैश्विक स्तर पर बाजार की स्थिति इसी तरह बनी रही तो भारत का गेहूं निर्यात 2022-23 में एक करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर को छू पाने में सफल हो सकेगा।

भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन होने के आंकड़े जारी किए गए हैं। देश में इस वर्ष 2021-22 में खाद्यानों का 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। जोकि पिछले साल 2020-21 की तुलना में 5.32 मिलियन टन ज्यादा है। यदि पिछले पांच सालों वर्ष 2016-17 से 2020-21 से तुलना की जाए तो यह 25.35 मिलियन टन ज्यादा है।

इस वर्ष चावल का भी रिकॉर्ड उत्पादन 127.93 मिलियन टन होने का अनुमान हैं। जोकि गत पांच वर्षों की तुलना में 11.49 मिलियन टन ज्यादा है। गेहूं का उत्पादन भी इस वर्ष 111.32 मिलियन टन होने की पूरी संभावना है। जोकि गेहूं के औसत उत्पादन 103.38 मिलियन टन से 7.44 मिलियन टन ज्यादा है। इसी प्रकार से दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन पिछले पांच सालों के उत्पादन 23.82 मिलियन टन से 3.14 मिलियन टन ज्यादा है। देश में इस वर्ष सरसों के क्षेत्रफल में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके चलते देश में तिलहन उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस वर्ष 2021-22 में 37.15 मिलियन टन रिकॉर्ड तिलहन उत्पादन होने जा रहा है। जो गत वर्ष के उत्पादन 35.95 मिलियन टन की तुलना में 1.20 मिलियन टन ज्यादा है। गन्ना उत्पादन में भी रिकॉर्ड 414.04 मिलियन टन उत्पादन गन्ना के औसत उत्पादन से 40.59 मिलियन टन ज्यादा हो रहा है। देश में यह रिकॉर्ड उत्पादन करोना जैसी महामारी के बावजूद होने जा रहा है, जो कि खेती और किसानी के लिए आपदा में किसी अवसर से कम नहीं है। कोविड-19 की आपदाओं के मध्य, भारत ने वैश्विक स्तर पर पूरी दुनियां के जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम योगदान दिया है।

अफगानिस्तान जैसे देश को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में भी भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान परिदृश्य में रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के कई देश भारत से गेहूं और अन्य खाद्यान्न की मांग कर रहे हैं। इसके चलते भारत से खाद्यान्न निर्यात बढ़ने का अवसर है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती खाद्यान्न निर्यात मांग का लाभ किसानों को भी मिल सके, केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। निश्चित रूप से इस समय देश में कृषि निर्यात को ऊचांईयों तक ले जाने की संभावनाएं हैं।

पशुपालकों और पशुधन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है बदलती जलवायु

पंकज शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार

बदलती जलवायु जहां एक ओर कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। वहीं दूसरी तरफ यह पशुपालकों और उनके पशुधन पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। इस बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते सदी के अंत तक भारत में डेयरी उत्पादन 45 फीसदी तक घट जाएगा। वहीं अमेरिका के डेयरी और मीट उत्पादन में करीब 6.8 फीसदी की गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का एक प्रमुख डेयरी उत्पादक देश है। जहां किसान अपनी जीविका के लिए काफी हद तक अपने मवेशियों पर निर्भर है। ऐसे में बढ़ता तापमान बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इस बारे में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा एक विस्तृत शोध किया गया है, जो अंतराष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट प्लैनेटरी अर्थ में प्रकाशित हुआ है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने मवेशियों पर बढ़ते तापमान के असर को समझने का प्रयास किया है और यह जानने की कोशिश की है कि इससे डेयरी उत्पादन (दूध और मीट) पर कितना असर पड़ेगा। उनके अनुसार तापमान में होती वृद्धि जब मवेशियों के सहन क्षमता से बढ़ जाएगी तो उसका असर उनके वजन, दुग्ध उत्पादन और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि इससे उत्पादकता पर प्रभाव न भी पड़े तो भी गर्मी से पैदा होता तनाव छोटी अवधि में ही सही, लेकिन इन जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में यह मुद्दा केवल पशु उत्पादन का ही नहीं बल्कि उनके कल्याण से भी जुड़ा है। अपने इस शोध में वैज्ञानिकों ने 2045 और 2085 तक जलवायु परिदृश्य एसएसपी 1- 2.5 और एसएसपी 5- 8.5 के तहत बढ़ते तापमान के आधार पर मवेशियों पर पड़ने वाले असर का पूर्वानुमान किया है। जिसमें यह बताया गया है कि बढ़ते तापमान के पशुओं के आहार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इससे डेयरी उत्पादन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है।

-किसानों की कंपनियों और दिल्ली की कंपनी के बीच एमओयू

विदेशों में आसानी से बिकेगा बालाघाट का चिन्नौर चावल

बालाघाट। संवाददाता

मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रथम जीआई टैग प्राप्त बालाघाट चिन्नौर चावल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और चिन्नौर चावल के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया गया। यह एमओयू एक जिला-एक उत्पाद योजना आधारित एफपीओ चिन्नौर वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, वारासिवनी और चिन्नौर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, लालबर्रा का दिल्ली की सत्सुमी फार्म्स (एलएलपी) कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया गया। एमओयू हाल ही में संपन्न शहद उत्पादन और काजू की खेती से संबंधित दो दिवसीय कार्यशाला में किया गया। समझौते के तहत दोनों एफपीओ के माध्यम से जिले के चिन्नौर उत्पादक किसानों की चिन्नौर का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विक्रय सुनिश्चित हो गया है। इस समझौते के बाद किसानों को चिन्नौर के विक्रय की समस्या खत्म होने के साथ अच्छे भाव मिलना तय हो गया। जिले में चिन्नौर उत्पादक किसानों की दो कंपनियां (एफपीओ) वारासिवनी और लालबर्रा विकासखंड में कार्यरत है, जो चिन्नौर के उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन का कार्य रही है।

प्राप्त हुआ इंपोर्टर-एक्सपोर्टर कोड-

जिले की चिन्नौर उत्पादक किसानों की दोनों कंपनियों को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डायरेक्टेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली से इंपोर्टर-एक्सपोर्टर कोड प्राप्त हो गया है। अब चिन्नौर चावल के विदेश निर्यात के रास्ते खुल गए हैं। यह एमओयू दोनों चिन्नौर उत्पादक एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सत्सुमी फार्म्स के प्रतिनिधि डॉ. प्रवीण सिंह ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया।

यह रहे मौजूद

एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान जिले के अग्रणी चिन्नौर उत्पादक कृषक गौरीशंकर बिसेन, अध्यक्ष, मप्र अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग व विधायक और दोनों एफपीओ के शेयरधारक चिन्नौर उत्पादक कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉ. एनके बिसेन, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, मुरझड़, उपसंचालक (कृषि) राजेश खोब्रागड़े, सहायक संचालक (उद्यानिकी) सीबी देशमुख, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरएल राउत, कृषि वैज्ञानिक डॉ. उत्तम बिसेन, डॉ. शरद बिसेन, डॉ. विक्रम सिंह गौर, सहायक उपनिरीक्षक मनोज पटले और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गुलाल से न त्वचा में खुजली फुंसी होंगी, न आंखें लाल

मुरैना में महिलाओं ने पलाश के फूलों से बनाया हर्बल गुलाल

मुरैना। संवाददाता

होली पर बाजार में आने वाले खतरनाक केमिकलों से बने रंगों के कारण त्वचा में कई प्रकार के एलर्जी हो जाती है। आंखों को भी नुकसान पहुंचाता हैं। ऐसे में जौरा जनपद पंचायत के सांकरा गांव की महिलाओं ने पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल बनाया है। यह गुलाल सस्ता होने के साथ-साथ एलर्जी से जुड़े रोगों से बचाने वाले हैं। जिले में कैलारस और पहाड़गढ़ क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाले पलाश के फूल (स्थानीय भाषा में टेसू के फूल) कहा जाता है, इन्हीं फूलों से जौरा क्षेत्र के सांकरा गांव की 10 से ज्यादा महिलाओं ने यह हर्बल गुलाल बनाया है। यह महिलाएं आजीविका मिशन द्वारा गठित किए गए बाबा साहब स्व सहायता समूह की सदस्य हैं, जिन्होंने पहले पेड़ों से फूल जुटाए। सुखाकर इन्हें बारीक पीसा। लाल रंग के इन फूलों से महिलाओं ने लाल, पीले, केसरिया, हरा व नीले कलर के हर्बल गुलाल बनाए हैं, इनके निर्माण में उपयोग हुए रंग भी पूरी तरह हर्बल है।

पैसा और पानी बचाएंगे - सांकरा गांव की महिलाओं ने 70 किलो से ज्यादा हर्बल गुलाल तैयार कर दिया है, जिसे होली पर मुरैना शहर के बाजार में खुद स्टाल लगाकर बेचेंगी। इसके लिए कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने आजीविका मिशन व मुरैना नगर निगम को निर्देश दिए हैं, कि हनुमान चौराहा व पुराने बस स्टैण्ड के पास हर्बल गुलाल के लिए स्टाल बनवाए जाएं। बाजार में जहां कई कंपनियों के गुलाल के 100 ग्राम के पैकेट के दाम 30 से 45 रुपए तक है, जबकि फूलों से बने यह हर्बल गुलाल 20 रुपए में 100 ग्राम है। यह गुलाल पानी की बचत भी करेंगे, क्योंकि होली खेलने के बाद यह केमिकल रंग-गुलाल की तरह त्वचा से नहीं चिपकते, बल्कि आसानी से शरीर से धुल जाते हैं।

इनका कहना है

पलाश के फूलों से हम बचपन में रंग व गुलाल बनाते थे। इस सीजन में यह फूल आसानी से मिल जाते हैं। होली पर गुलाल की मांग भी होती है, इसीलिए यह आइडिया आया। होली पर आने वाले रंग नुकसानदायक, महंगे होते हैं। उनकी तुलना में हर्बल गुलाल सस्ता है, अगर लोगों को पसंद आया तो इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे।

नर्मदा बाई, हर्बल गुलाल बनाने वाली समूह की अध्यक्ष

सांकरा गांव की महिलाओं ने जो हर्बल गुलाल बनाया है वह बेहद अच्छा है। मैं खुद इसी गुलाल से होली खेलूंगा और अपने परिवार व परिचितों को भी यही गुलाल दूंगा। जिले में पहली बार फूलों से इस प्रकार का गुलाल बना है। यह सस्ता है, इससे होली खेलने पर पानी का खर्च कम होता है।

रोशन कुमार सिंह, सीईओ, जिला पंचायत, मुरैना

तेज हवा व बारिश से खेतों में फसल आड़ी पड़ी

पके गेहूं ने खो दी चमक उत्पादन पर फिरा पानी

उज्जैन। संवाददाता

जिले में इस बार गेहूं की फसल अच्छी थी। चमक वाला गेहूं लहलहाने लगा था कि बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओले व तेज हवा के साथ हुई बरसात से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई। उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। वहीं, गेहूं ने चमक भी खो दी है , जिससे भाव कम मिलेगा। तेज बारिश ने जिले अनेक क्षेत्रों में गेहूं की फसल को नुकसान पंहुचाया है। बड़नगर, घट्टिया, तराना क्षेत्र में खेतों में खड़ी फसल आड़ी पड़ गई। जवासिया के किसान अजय पटेल ने बताया कि बीती रात की बारिश से गेहूं, लहसुन आलू का उत्पादन प्रभावित होगा। सरकार को सर्वे करवाकर आर्थिक नुकसान की भरपाई करना चाहिए। चिकली के किसान रामसिंह पटेल ने बताया कि बड़नगर तहसील के गांव में भी भारी बारिश हुई है जिससे गेहूं में नुकसान हुआ है। घट्टिया, तराना क्षेत्र के किसान जगदीश आंजना ने भी कहा कि बेमौसम बारिश से गेहूं को काटने में परेशानी आएगी। गेहूं के साथ मिट्टी भी आने से मंडी में भाव कम मिलेंगे।

ओलावृष्टि का मामला विधानसभा में उठाया

वर्षा, ओलावृष्टि व तेज आंधी से खेतों में खड़ी फसल नष्ट होने पर सर्वे कराकर बीमा व राहत राशि प्रदान करने का मामला विधानसभा में विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने उठाया। शून्य काल की सूचना के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि नागदा-खाचरौद क्षेत्र में विगत दिनों हुई धुआंधार बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी, तूफान से क्षेत्र के अनेक गांवों में किसानों की खड़ी गेहूं की फसल पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। क्षेत्र के ग्राम चंदवासला, निमाड़ी, बड़गांव, भीकमपुर, नंदवासला, सनासला, बरामदखेड़ा, नंदियासी, अंतलवासा, दुपड़ावदा, बरलई, नरसिंहगढ़, खेड़ावदा, कनवास, भुंवासा, बरथून, राजपुर रायती, कमठाना, मड़ावदा, मड़ावदी, दुपड़ावदा, छोटा चिरोला, बेड़ावन्या आदि गांव शामिल हैं।

कृषि-प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर काम होगा

औषधीय पौधों पर अनुसंधान और विकास के लिए नई साझेदारी

भोपाल/नई दिल्ली। औषधीय पौधों की खेती और अनुसंधान को को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक साथ आए हैं। इस पहल से औषधीय पौधों के जरिए मूल्य संवर्धित उत्पादों से संबंधित कृषि-प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर काम होगा। अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के साथ भारत स्वास्थ्य, कृषि, और कई अन्य क्षेत्रों में मूल्यवान वैज्ञानिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह समृद्ध विरासत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ सहयोग एवं एकीकरण के माध्यम से भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने की क्षमता रखती है। इस संबंध में, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-पक्षीय हितधारकों के परस्पर सहयोग की जरूरत को देखते हुए यह पहल की गई है। आयुष मंत्रालय, आईसीएआर और सीएसआईआर के बीच हुए इस करार का मुख्य उद्देश्य भारत की पारंपरिक कृषि पद्धतियों के महत्व को रेखांकित करना है, और देश में सामाजिक-आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इन पर आधारित हस्तक्षेपों को मान्य और लागू करने के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करना है।

डालनी होगी स्वस्थ भोजन की आदत

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने वृक्षायुर्वेद, मृगायुर्वेद आदि के रूप में मूल्यवान पारंपरिक ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि न केवल मनुष्य, बल्कि पौधों और जानवरों के लाभ के लिए एकीकृत कृषि की दिशा में पारंपरिक विज्ञान और प्रथाओं को मान्य करने में यह सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आयुष मंत्रालय की आयुर्वेद आहार पहल एवं साल 2023 के अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष और भारत के पारंपरिक आहार का उल्लेख करते हुए स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए तीनों पक्षों की क्षमता को भी रेखांकित किया। डॉ. त्रिलोचन महापात्र, महानिदेशक, आईसीएआर और सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, ने इस साझेदारी को खाद्य और कृषि पर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है।

मध्यप्रदेश कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा 1.72 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

किसानों पर मेहरबान शिवराज सरकार

गरीब के अलावा नौजवान, किसान और महिला-बेटियां शिवराज सरकार ने इस बजट में इन चारों वर्गों को साधने की कोशिश की है। वजह साफ है- 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव। शिवराज जानते हैं, इन चारों को अपने पाले में कर लिया तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती इन तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने की है। प्रदेश में किसानों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। भले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, लेकिन शिवराज सरकार ने इस वर्ग के लिए बजट में सबसे ज्यादा 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

भोपाल।

सरकार ने कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2022-23 में 40 हजार 916 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मछली पालन शामिल है। इस वर्ष जहां राज्य सरकार ने पहले से चली आ रहीं कई योजनाओं को आगे भी जारी रखा है। वहीं कई नई योजनाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। किसान समाधान मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में कृषि एवं संबंधित के लिए किए गए प्रस्तावों को लेकर आया है। प्रदेश में 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मौजूद है। बजट में इसे साल 2025 तक बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। सरकार कृषि निर्यात योजना की शुरुआत भी करेगी। इसके अलावा एक जिला, एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलों में किसी एक फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

गांव की तरफ चली सरकार

बजट में ग्रामीण विकास पर फोकस किया है। प्रदेश की 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा आबादी के लिए शिवराज सरकार ने 27,925 करोड़ का प्रावधान रखा है। पिछले बजट की तुलना में यह राशि 74 प्रतिशत ज्यादा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए विधायकों से 15 करोड़ के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव सरकार ने मांगे थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ग्रामीण इलाकों ज्यादा राशि खर्च करेगी। इसके उलट शहरी विकास के लिए बजट पिछले साल की तुलना में 1 प्रतिशत कम कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ। शहरों की विकास योजनाओं के लिए 13,113 करोड़ का प्रावधान किया है।

रोजगार-उद्यम क्रांति पर फोकस

सरकार का फोकस स्व-रोजगार पर ज्यादा है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार अब उद्यम क्रांति योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों के लिए लागू योजनाओं के लिए बजट में 1 हजार करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है।

उम्मीदों को लगे पंख

- **चिकित्सा शिक्षा:** एमबीबीएस सीटें 2,035 से बढ़कर 3,250 होंगी
- **बिजली:** अब सागर, छतरपुर और ओंकारेश्वर में लगेंगे सोलर प्लांट
- **पेंशन का टेंशन:** मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं
- भोपाल, जबलपुर में चार्जिंग स्टेशन, नरसिंहपुर, कटनी को औद्योगिक पार्क की सौगात
- दो लाख 79 हजार 237 करोड़ का बजट, प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया
- शिक्षाविदों ने सराहा, बोले- शालेय शिक्षा के उन्नयन में मिलेगी मदद
- कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा

नए औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित

मध्यप्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनमें 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने बजट में निर्माण से जुड़ी योजनाओं के लिए 42 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ऊर्जा विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए 16 हजार करोड़ रखे गए हैं। जबकि सड़क व पुलों के लिए लोक निर्माण विभाग को साढ़े 5 हजार करोड़ राशि दी जा रही है।

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प

भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्राविधान। 4000 किमी सड़के बनाने का लक्ष्य इस साल। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है।

जल जीवन मिशन प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश में राजस्व घाटा 18356.22 करोड़ रहा। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआई टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गौ-संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाए शुरू की जाएगी।

शरबती गेहूं को मिलेगा जीआई टैग

देवड़ा ने कहा कि चिन्नोर धान को जीआई टैग मिल चुका है। शरबती गेहूं, पिपरिया तुअर दाल, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल को जीआई टैग दिलाने की कोशिश चल रही है। सरकार ने प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को टारगेट किया जा रहा है।

ग्रामीण स्व सहायता समूहों के लिए योजना

ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए योजनाओं को वृहद स्वरूप में क्रियान्वित करने के लिए 1100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। जो कि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से लगभग 141 प्रतिशत अधिक है। मनरेगा का बजट अनुमान वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत बढ़ाकर 3500 करोड़ प्रस्तावित है। इस वर्ष 26 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। वहीं वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20 प्रतिशत उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

मछली पालन की नई योजना

राज्य में मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्यपालन विकास योजना प्रारम्भ की जाएगी। इस योजना के लिए इस वर्ष बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सहकारी संस्थाओं में किया जाएगा निवेश

सहकारी संस्थाओं की किसानों को खाद, बीज, ऋण उपलब्ध कराने तथा उपार्जन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अंशपूंजी को बढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। साथ ही जैविक कृषि, उद्यानिकी, पर्यटन, ऊर्जा आदि के लिए सहकारी आंदोलन का विस्तार किया जा रहा है।

सिंचित क्षेत्र का बढ़ाया जाएगा

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। सिंचाई क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 9 हजार 267 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। राज्य में वर्ष 2025 तक सिंचाई का क्षेत्रफल 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा समय में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 23 लाख 21 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 वृहद्, 46 मध्यम एवं 288 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 20 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

ऊर्जा के लिए बजट में प्रावधान

ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा तथा किसानों को 24 घंटे बिजली मिल सके इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 23 हजार 255 करोड़ का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष इस क्षेत्र के लिए 17 हजार 908 करोड़ का प्रावधान किया गया था। राज्य में कृषि में सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष भी किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली दी जाएगी। गैर कृषि कार्यों के लिए 24 घंटे विद्युत देने का लक्ष्य बजट में रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दे रही है।

पशुपालन की नई योजना

मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस क्षेत्र में और अधिक उत्पादन

तथा रोजगार सृजन के लिए एक अलग से योजना की शुरुआत करने की घोषणा बजट में की गई है। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके लिए 150 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है।

घर पर होगा पशुओं का इलाज

पशुओं का उपचार पशुपालकों के पास घर-घर जाकर हो सके, इस के लिए भारत सरकार द्वारा

एक नई योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में 406 नए पशु चिकित्सा वाहन दिए जाएंगे। पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक तथा सहयोगी, घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के लिए 142 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

कृषि उत्पादों के निर्यात की नई योजना

राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत जिलों का चयन कर विशेष फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अब सरकार इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में एक नई योजना निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित रखने हेतु एक लाख मीट्रिक टन के भंडारण की क्षमता चरणवद्ध तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है।

कृषि की नई योजनाएं होंगी शुरू

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कृषि के विकास एवं किसानों के कल्याण के लिए मांग आधारित कृषि विविधीकरण, जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रचार-प्रसार, एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना, मध्य प्रदेश की विशिष्ट फसलों/किस्मों के लिए जीआई टैग, मप्र मिलेट मिशन, कृषक उत्पादन संगठनों का गठन एवं संवर्धन, कृषि फसलों के निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

राज्य सरकार का लक्ष्य, एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। हम योजनाबद्ध तरीके से लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को लक्षित कर कार्य कर रहे हैं। पहले से ही मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती के मामले में शीर्ष राज्यों में से एक है।

सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पेश किए गए बजट के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अभी इसी वर्ष किसानों को 7618 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में दिया गया है। इसके पहले 3 हजार करोड़ रुपए आरबीसी 6-4 में देने का काम किया गया है। इस बजट में भी फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

हमारा वादा, किसानों की फसल की पूरी खरीद करेंगे, जो हमने निभाया

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों से उनकी उपज का समर्थन मूल्य पर खरीद करना हमारी सवोच्च प्राथमिकता है। हमारा वादा रहा है कि हम किसानों की फसल की पूरी खरीद करेंगे, जो हमने निभाया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद में किसानों के साथ ही खरीद संस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। अगर खरीद संस्थाओं को हानि होती है तो उसकी पूर्ति के लिए इस बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

किसान प्रदेश के अन्नदाता और भाग्य विधाता: देवड़ा

देवड़ा ने कहा कि किसान प्रदेश के अन्नदाता और भाग्य विधाता हैं। हमारी कोशिश खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कायज्काल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 17 हजार करोड़, फसल खरीद में लगभग 66 हजार करोड़, शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण लगभग 30 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी लगभग 30 हजार करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 हजार 337 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 569 करोड़ और अन्य कई योजनाओं में 2 लाख 72 हजार करोड़ से अधिक की सहायता राशि किसानों को दी गई है।

नई योजनाओं को शुरू करने की तैयारी

इस साल के बजट में किसानों के हित में कई योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मांग आधारित कृषि विविधीकरण, जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रचार-प्रसार, एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना, विशिष्ट फसलों व किस्मों के लिए जीआई टैग, मध्य प्रदेश मिलेट मिशन, किसान उत्पादन संगठनों का गठन एवं संवर्धन और कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाओं को शुरू करने की तैयारी कर रही है।

आसंदी के सामने विपक्ष का हंगामा

प्रदेश के हर अंचल के संतुलित विकास का बजट

यह आत्मनिर्भर मप्र के निर्माण का बजट है। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का बजट प्रदेश की नई तस्वीर बनाएगा। यह सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। सर्वव्यापी अर्थात प्रदेश के हर अंचल के संतुलित विकास का यह बजट है। सर्वस्पर्शी भी, जिसमें गरीबों के आवास, बच्चों की शिक्षा, पेयजल और इलाज की व्यवस्था के साथ किसानों के कल्याण का भी ध्यान रखा गया है।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सर्वे भवंतु सुखिनः का संकल्प दर्शाता बजट

वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट शिवराज सरकार के सर्वे भवंतु सुखिनः के संकल्प को दर्शाता है। हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रस्तुत सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी यह बजट मप्र के विकास को नई गति प्रदान करेगा। इस बजट की सबसे सुखद बात यह है कि तमाम खर्चों के बावजूद बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार का फोकस बच्चों की पर है। पहले चरण में सरकार 360 सीएम राइज स्कूल शुरू करने जा रही है। प्रदेश के स्कूलों में 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी।

कमलनाथ, पूर्व सीएम

बजट सिर्फ झूठ और गुमराह का पुलिंदा

शिवराज सरकार का बजट सिर्फ झूठ और गुमराह का पुलिंदा है। यह जनता को धोखा देने वाला बजट है। इसमें सिफ कागजी प्रावधान किए गए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए एक बार फिर झूठे सपने दिखाए गए हैं। प्रदेश की 85 फीसदी ओबीसी-एससी-एसटी वर्ग की आबादी के युवाओं को रोजगार देने के लिए मात्र 150 करोड़ का प्रावधान किया है।

कमलनाथ, पूर्व सीएम

कैसे और कब करें, कितनी होगी कमाई, कृषि वैज्ञानिक ने दी पूरी जानकारी

अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान करें पपीते की खेती

भोपाल। संवाददाता

पपीता मार्च-अप्रैल में पपीत लगने लगते हैं। इस समय लगाए गए पपीता की फसल में विषाणु जनित एवं फफूंद जनित रोग कम लगते हैं। मार्च का महीना चल रहा है का महीना चल रहा है इसलिए अधिकांश किसान पपीता की नर्सरी की तैयारी कर चुके होंगे या तैयारी कर लें। नर्सरी एक ऐसा स्थान है जहां पौधे, जहां ऊंची जमीन में रोपने से पहले उगाए जाते हैं। बीज की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके आधार पर पपीते जैसी फलों के लिए पहले नर्सरी में पौधे उगाते हैं, फिर मुख्य भूखंड में प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, बीज को नर्सरी में बोने के बाद महीन मिट्टी की एक परत के साथ ढक दिया जाता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर, बिहार के अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक एवं एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर एसके सिंह के अनुसार इस प्रकार करें पपीते की खेती। डॉक्टर एसके सिंह अनुसार पपीता की खेती करने वाले किसानों के नर्सरी तैयार करना जरुरी है। नर्सरी बनाने से पहले जमीन का चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है जैसे क्षेत्र जलभराव से मुक्त होना चाहिए। वांछित धूप पाने के लिए हमेशा छाया से दूर रहना चाहिए। नर्सरी क्षेत्र पानी की आपूर्ति के पास होना चाहिए। क्षेत्र को पालतू जानवरों और जंगली जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए।

यदि संभव हो तो प्लास्टिक टनल से ढकी जुताई वाली मिट्टी पर लगभग 4-5 सप्ताह तक मिट्टी का सोलराइजेशन करना बेहतर होता है। बोवनी के 15-20 दिन पहले मिट्टी को 4-5 लीटर पानी में 1.5-2 प्रतिशत फार्मेलिन घोल कर प्रति वर्ग मीटर की मात्रा में मिलाकर प्लास्टिक शीट से ढक दें। कैप्टन और थीरम जैसे कवकनाशी 2 ग्राम /लीटर की दर से घोल बना कर मिट्टी के अंदर के रोगजनकों को भी मार देना चाहिए। फुराडॉन, हेप्टाक्लोर कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जिन्हें सूखी मिट्टी में 4-5 ग्राम/वर्ग मी की दर से मिलाया जाता है और नर्सरी तैयार करने के लिए 15-20 सेंटीमीटर की गहराई तक मिलाया जाना चाहिए। ढकी हुई पॉलीथीन शीट के नीचे कम से कम 4 घंटे लगातार गर्म भाप की आपूर्ति करें और मिट्टी को बीज बिस्तर तैयार करते हैं।

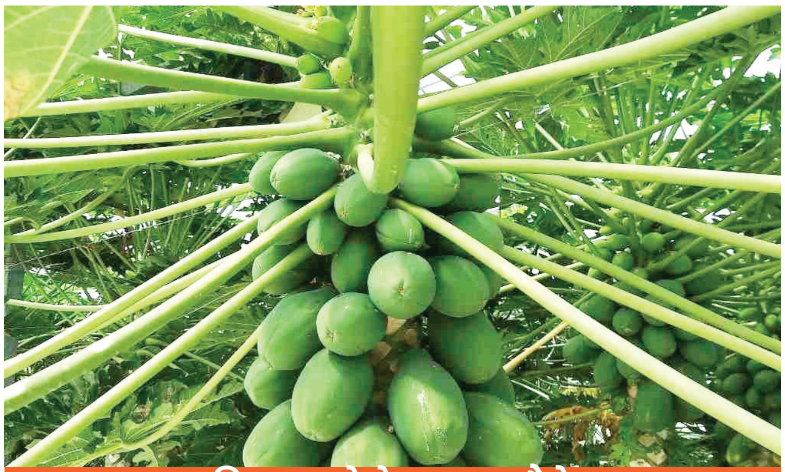

किसान ऐसे लगाएं पौधे

एक एकड़ के लिए 4050 वर्ग मीटर जमीन में उगाए गए पौधे काफी होते हैं। इसमें 2.5 × 10 × 0.5 मीटर आकार की क्यारी बनाकर उपरोक्त मिश्रण अच्छी तरह मिला दें, और क्यारी को ऊपर से समतल कर दें। इसके बाद मिश्रण की तह लगाकर 1/2% गहराई पर 3% × 6% के फासले पर पंक्ति बनाकर उपचारित बीज बो दे और फिर 1/2% गोबर की खाद के मिश्रण से ढक कर लकड़ी से दबा दें ताकि बीज ऊपर न रह जाए। यदि गमलों बक्सों या प्रोट्रे का उगाने के लिए प्रयोग करें तो इनमें भी इसी मिश्रण का प्रयोग करें। बोई गई क्यारियों को सूखी घास या पुआल से ढक दें और सुबह शाम फव्वारे द्वारा पानी दें। बोने के लगभग 15-20 दिन भीतर बीज जम जाते हैं। जब इन पौधों में 4-5 पत्तियां और ऊंचाई 25 सेमी. हो जाए तो दो महीने बाद मुख्य खेत में प्रतिरोपण करना चाहिए, प्रतिरोपण से पहले गमलों को धूप में रखना चाहिए।

बीज का चयन

पपीते के उत्पादन के लिए नर्सरी में पौधों का उगाना बहुत महत्व रखता है। इसके लिए बीज की मात्रा एक हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम पर्याप्त होती है। बीज पूर्ण पका हुआ, अच्छी तरह सूखा हुआ और शीशे की जार या बोतल में रखा हो जिसका मुंह ढका हो और 6 महीने से पुराना न हो, उपयुक्त है। बोने से पहले बीज को 3 ग्राम केप्टान से एक किलो बीज को उपचारित करना चाहिए।

इस तरह से किसान बनाएं कंपोस्ट

बीज बोने के लिए क्यारी जो जमीन से ऊंची उठी हुई संकरी होनी चाहिए इसके अलावा बड़े गमले या लकड़ी के बक्सों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए पत्ती की खाद, बालू, तथा सडी हुई गोबर की खाद को बराबर मात्र में मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेते हैं। जिस स्थान पर नर्सरी हो उस स्थान की अच्छी जुताई, गुड़ाई करके समस्त कंकड़-पत्थर और खरपतवार निकाल कर साफ़ कर देना चाहिए । वह स्थान जहां तेज धूप तथा अधिक छाया न आए चुनना चाहिए।

दवा के साथ सलाद और सब्जी में भी हो रहा इस्तेमाल

सतावरी की खेती से किसान कर सकते हैं मोटी कमाई

भोपाल। संवाददाता

हमारे देश में सतावरी का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है। इसे अपने देश में शतावरी के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इसकी जड़ों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। बदलते समय में स्वास्थ्य के प्रति रुझान बढ़ने से इसकी नई कोपलों का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में होने लगा है। विदेशी व्यंजनों में इसके इस्तेमाल से किसानों के लिए कमाई का यह एक नया जरिया बन गया है। औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए अब इसकी जड़ और नई पौध से भी मुनाफा मिलना शुरू हो गया है। सबसे खास बात है कि यह एक बहुवर्षीय पौधा है। एक बार लगाने पर कई साल तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है। एस्पेरेगस से किसान 10 साल तक पैदावार ले सकते हैं। इसमें फोलेट, क्रोमियम, फाइबर, विटामिन ए, सी, ई और के पाया जाता है। बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी खेती का दायरा भारत में धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। आज भारत के लगभग हर हिस्से में इसकी खेती हो रही है। मौजूदा समय में भारत में इसकी खेती जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रमुखता से हो रही है।

इन बातों का रखें ध्यान

सतावरी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में पैदावार अधिक मिलती है। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एके सिंह बताते हैं कि ढीली मिट्टी होगी तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ज्यादा स्प्राउट्स निकलेंगे। किसान सतावरी के पौधे पुरानी जड़ों और बीजों से तैयार कर सकते हैं। बीजों से पौध तैयार करने के लिए नर्सरी लगानी पड़ती है। एक हेक्टेयर खेत में स्पेरेगस के पौधे लगाने के लिए 7 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। किसान चाहे तो नसर्जी से पौधे खरीदकर भी रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी में बीज लगाने के 45 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे तैयार खेत में मेड़ों पर रोपा जाता है। रोपाई के करीब डेढ़ साल बाद जड़ तैयार हो जाती है। वहीं अगर किसान सब्जी और सलाद के लिए खेती कर रहे हैं तो जल्द ही पैदावार मिलने लगती है। बाजार मांग के हिसाब से किसान अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर वे दवा बनाने वाली कंपनियों को बेचना चाहते हैं तो उन्हें आमदनी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जबकि सलाद और सब्जी के मामले में ऐसा नहीं है।

रीवा पशुचिकित्सा कॉलेज के डॉक्टरों ने बताए उपचार-बचाव, बोले -दूषित चारे, दाने के सेवन होता है रोग का फैलाव

मुंहपका-खुरपका रोग छोटी उम्र के पशुओं के लिए जानलेवा

रीवा। मुंहपका-खुरपका रोग मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी और शूकर जाति के पशुओं होने वाला विषाणुजनित, अत्यन्त संक्रामक, छूतदार व अतिव्यापी रोग है। छोटी उम्र के पशुओं में यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। संकर नस्ल के पशुओं में यह रोग अत्यन्त तीव्रता से फैलता है। इस रोग में मृत्युदर तो कम है, लेकिन दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इस रोग का फैलाव पशुपालक को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। यह बात पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान महाविद्यालय रीवा की डॉ. शिल्पा गजभिये, डॉ. कविता राय, डॉ. प्रतिभा शर्मा, डॉ. ब्रजेश सिंह ने एक चर्चा के दौरान कही। वहीं डॉ. शिल्पा के अनुसार रोग का फैलाव दूषित चारे, दाने व पानी के सेवन से होता है। रोगी पशु की बिछावन के संपर्क में आने से, गोबर व पेशाब से, दुधारू पशुओं के ग्वाले से और हवा के माध्यम से रोग का फैलाव होता है। उन्होंने बताया कि रोग के लक्षण 105-107 ए फॉरेनहाइट तक तेज बुखार आना। मुंह, मसूड़े व जीभ पर छाले, लगातार लार का गिरना। पैरों में खुरों के बीच छाले जिससे पशु का लंगडाना। पैर के छालों में जख्म एवं कीड़े पड़ना। दुधारू पशु के थनों में छाले पड़ना। कुछ पशुओं में हांफने की बीमारी होना। दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन में एकदम कमी आना। जैसी बातें रोग के मुख्य लक्षण हैं। डॉ. शिल्पा ने बताया कि इन बातों से पशुपालकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन बीमारियों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। रोगों के उपचार के लिए सबसे पहले मुंह एवं खुर के घावों को प्रतिदिन सुबह-शाम फिटकरी या लाल दवा हल्के घोल से सफाई करें। घाव में कीड़े पड़ने पर फिनाइल तथा मीठे तेल की बराबर मात्रा मिलाकर उपयोग करें। उपरोक्त सब उपलब्ध न होने पर नीम के पत्ते उबालकर ठंडे किए पानी से जख्म साफ करें। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों का सही इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है। अत: बचाव ही उपचार है। इस रोग से पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से अन्य रोगों के बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार कराएं।

रोग की रोकथाम व बचाव

डॉ. शिल्पा ने बताया कि पशुओं में प्रतिवर्ष नियमित रूप से टीकाकरण कराना चाहिए। यह रोग महामारी के रूप में फैलता है अत: रोगी पशु को स्वस्थ पशु से तुरन्त अलग करें। पशु को बांधकर रखें व घूमने-फिरने न दें। बीमार पशु के खाने-पीने का प्रबंध अलग ही करें। रोगी पशुओं को नदी, तालाब, पोखर आदि में पानी न पीने दें। पशु को सूखे स्थान पर बांधे। कीचड़, गीली व गंदी जगह पर नहीं। रोगी पशु को संभालने वाले व्यक्ति को बाड़े से बाहर आने पर हाथ-पैर साबुन से अच्छी तरह से धो लेने चाहिए।

संक्रमि पशु को खुले में न छोड़ें

उन्होंने बताया कि मुंहपका-खुरपका रोग से संक्रमित पशु को बेचना, गांव के अन्य पशुओं एवं अन्य गांव के पशुओं के लिए भी खतरा है। अत: पशुओं को न बेचें और न ही खरीदें। पशु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन नहीं करें। रोग की सूचना तुरन्त पशु चिकित्सालय में दें। जहां-जहां पशु की लार आदि गिरती है, वहां पर कपड़े धोने का सोडा/चूना इत्यादि डालते रहें, यदि संभव हो तो फिनाइल से धोना भी लाभप्रद होता है। फिड़किया भेड़-बकरियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। यह बीमारी स्वस्थ भेड़ व बकरियों में मुख्यतया जुलाई-अगस्त माह में होती है। यह बीमारी हर उम्र की भेड़ व बकरियों में प्राणघातक रोग के रूप में होती है। दरअसल, यह बीमारी एक जीवाणु से होती है। यह रोग भेड़-बकरी की प्रत्येक नस्ल, आयु तथा लिंग के पशु को प्रभावित करता है। अधिक प्रोटीन युक्त खुराक लेने अथवा ताजी फसल कटे हुए खेतों में चराने से यह बीमारी अधिक होती है। सरसों व चने की कटाई के तुरंत बाद खाली खेतों में बकरियों/भेड़ों को चराना सबसे अधिक हानिकारक होता है।

किसानों के लिए बकरी पालन हो सकता है फायदेमंद

बकरी पालन: कम लागत में ज्यादा मुनाफा

भोपाल। संवाददाता

देश में पशुपालन का व्यवसाय बहुत ही तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। पशुपालन के बिजनेस में आज भी लोग बकरी पालन को उत्तम व्यवसाय मानते हैं। किसानों के लिए तो यह व्यवसाय बेहद लाभकारी है, क्योंकि गाय-भैंस की तुलना में बकरी व्यवसाय लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। वैसे देखा जाए, तो भारत में 50 से अधिक बकरी पालन की नस्ले मौजूद हैं, लेकिन इन 50 नस्लों में से कुछ ही नस्लों का पालन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। तो आइए आज हम इस लेख में बकरियों की 5 उन्नत नस्लों के बारे में जानते हैं, जिन्हें पालकर आप कुछ ही समय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण- आज के इस आधुनिक समय में बकरी पालन का व्यवसाय बहुत ही तेजी से फैल रहा है। क्योंकि इस बिजनेस में लागत के साथ मेहनत भी कम लगती है। आप यह भी कह सकते हैं कि बकरी पालन का व्यवसाय आप कम पैसे में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफसे कई योजनाएं चलाई जाती हैं और साथ ही इसके लिए कई संस्थाएं प्रशिक्षण भी देती हैं। तो आइए आज हम इस लेख में बकरी पालन के प्रशिक्षण के बारे में जानते हैं।

ऐसे लें बकरी पालन का प्रशिक्षण- आपको बता दें कि सरकार पशुपालक भाइयों को आत्मनिर्भर और उन्हें अधिक लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह, मथुरा (उप्र) द्वारा बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान पशुपालकों को नई-नई तकनीक के बारे में विस्तार से बताया जाता है। जिससे वह अपने व्यवसाय में लाभ कमा सके। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान आपको बकरी पालन से लेकर उनके आवास प्रबंधन, आहार व्यवस्था, बीमारियों और उनकी रोकथाम की संपूणङ जानकारी के बारे में बताया जाता है।

बकरियों की 5 उन्नत नस्ल

1. **जमुनापारी नस्ल:** जमुनापारी बकरी की नस्ल को बिजनेस के लिए बेहद ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह कम चारे में भी अधिक दूध देती है। यह हर रोज लगभग 2 से 3 लीटर तक दूध देती है। बाजार में इस नस्ल की बकरी की अधिक मांग होती है, क्योंकि इसे दूध और मांस में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इस नस्ल की बकरी की कीमत बाजार में लगभग 10 से 15 हजार रुपए तक होती है।
2. **बीटल नस्ल:** बीटल नस्ल की बकरी को पशुपालक दूध और मांस के लिए पालते हैं। यह बकरी भी प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक दूध देती है। इसकी कीमत भी बाजार में लगभग 10 से 15 हजार रुपए तक है।
3. **सिरोही नस्ल:** सिरोही नस्ल की बकरी को पशुपालक सबसे अधिक पालते हैं, क्योंकि यह बकरी बहुत ही तेजी से बढ़ती है और बाजार में इसके मांस की सबसे अधिक मांग होती है। साथ ही इसमें दूध की क्षमता में सबसे अधिक होती है। इस नस्ल की बकरी को आप अनाज खिलाकर भी आसानी से पाल सकते हैं।
4. **उस्मानाबादी नस्ल:** इस नस्ली को पशुपालक भाई मांस व्यवसाय के लिए पालते हैं, क्योंकि उस्मानाबादी नस्ल की बकरी में दूध की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इसके मांस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इसका बाजार में सबसे महंगा बिकता है। बाजार में उस्मानाबादी नस्ल की एक बकरी की कीमत 12 से 15 हजार तक है।
5. **बरबरी नस्ल:** इस नस्ल को आप आसानी से कहीं भी पाल सकते हैं। इसके लिए कुछ अधिक आपको करने की जरूरत नहीं होती है।

बकरी पालन के प्रशिक्षण के लिए जरूरी बातें

» आपको भारत का नागरिक होना चाहिए।
» सरकारी संस्थाओं के द्वारा बकरी पालन का प्रशिक्षण लगभग7 दिनों तक चलता है।
» हर 2 महीने में इस प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
» प्रशिक्षण के लिए आवेदन शुल्क यानी पंजीकरण 5500 रुपए है और साथ ही संस्थाओं में ठहरने के लिए आपको 50 रुपए प्रतिदिन देने होंगे।
» प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया
» प्रशिक्षण के लिए आपको सबसे पहले केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी) की आधिकारिक साईट पर जाना होगा।
» इसके बाद आपको समक्ष होम पेज पर ट्रेनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा।
» जहां आपको ट्रेनिंग आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इस फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को विस्तार से भरें।
» इसके बाद आप इसे निदेशक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा उत्तर प्रदेश 221166 पर भेजें।
» ध्यान रहे कि प्रशिक्षण तिथि के दौरान ही आप बकरी पालन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पशुओं में दुग्ध क्षमता बढ़ाने के लिए आ गई 'चॉकलेट'

भोपाल। संवाददाता

जैसे कि हम इंसानों की खाने की चॉकलेट होती है। ठीक उसी तरह से पशुओं की भी खाने की चॉकलेट होती है। जिसके अंदर कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो पशुओं को अंदर से शक्तिशाली बनाती है। पशुपालक भाइयों को खुद कृषि विज्ञान केंद्र अपने पशुओं को चॉकलेट खिलाने के प्रति जागरूक करती रहती है। आपको बता दें कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के द्वारा बनाई गई इस यूएमएमबी पशु चॉकलेट को पशुओं के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। केवीके के वैज्ञानिक के मुताबिक, प्रतिदिन एक पशु को 500 से 600 ग्राम इस चॉकलेट को खिलाना चाहिए। इस चॉकलेट को बनाने के लिए इसमें चोकर, सरसों की खल, यूरिया, कैल्शियम, मैग्निशियम, जिंक, कॉपर, नमक आदि का इस्तेमाल होता है। भारतीय बाजार में पशु चॉकलेट की कीमत लगभग 80 रुपए है।

युवाओं के लिए स्वरोजगार का साधन- लोगों को इस चॉकलेट के प्रति जागरूक और साथ ही गांव में सरकार की तरफ से लोगों को रोजगार देने के लिए इस चॉकलेट की विधि को बनाने के लिए सरकार की तरफसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे ग्रामीण युवा अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सके और अपने गांव में रह कर ही अच्छा लाभ कमा सके।

पशु चॉकलेट के फायदे

» पशुओं में इसके सेवनसे बांझपन के खतरे से बचाया जा सकता है और साथ ही इसे खाने से पशुओं में प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी होती है।
» इसका प्रयोग पशुओं में हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए भी किया जाता है।
» इसके सेवन से पशुओं का पाचन तंत्र ठीक रहता है और फिर वह खोर व दीवार को नहीं चाटते हैं।
» इसके अलावा यह चॉकलेट पशुओं के दूध का व्यवसाय करने वाले पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि पशुओं को इस चॉकलेट को खिलाने से उनके दूध देने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है।
» इससे पशुओं में प्रोटीन की मात्रा को पूरा किया जाता है।
» यह चॉकलेट पशुओं में हार्मोन को संतुलन बनाए रखने में बेहद मददगार साबित होती है।

भोजपाल महोत्सव मेले में बॉलीबुड प्लेबैक सिंगर फरहान साबरी ने बांधा समा

32 दिनों तक चलने वाले मेले में सांस्कृतिक आयोजनों की बिखर रही छटा, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग

भोपाल। संवाददाता

भेल दशहरा मैदान पर चले रहे भोजपाल महोत्सव मेले में प्लेबैक सिंगर फरहान साबरी ने अपनी प्रस्तुति दी। साबरी ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद स्वरकोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके द्वारा गाए गए गीत मेरी आवाज ही पहचान है, चेहरा बदल जाएगा की प्रस्तुति दी। इस दौराना साबरी ने तुम्हे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मेरे रश्के कमर, ऐ वतन तेरे लिए जैसे गानों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए दर्शकों का प्रवेश नि:शुल्क रखा गया था। रात 8 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा और मप्र रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मेला अध्यक्ष सुनील यादव, मेला संयोजक विकास वीरानी के साथ ही मेला टीम मौजूद रही। बता दें कि फरहान साबरी बॉलीबुड की कई फिल्मों में गीत गा चुके हैं। ये बॉलीबुड के सबसे बड़े मिर्ची म्यूजिक अवॉर्ड में तीन बार विजेता रह चुके हैं। साबरी फिल्म पद्मावती में एक दिल एक जान, आयात, बाजीराव मस्तानी में तू मस्तानी तू दिवानी है, यमला पगला दीवाना टू, जिला गाजियाबाद जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज देकर लोगों का दिल जीत चुके हैं।

शहरवासियों के मनोरंजन का रखा जा रहा ख्याल

मेला समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि भोजपाल महोत्सव मेला में शहर वासियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर फरहान साबरी द्वारा प्रस्तुति दी गई। आने वाले दिनों में भी मेले के सांस्कृतिक मंच पर इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे, ताकि शहरवासियों का स्वस्थ्य मनोरंजन हो सके।

मेले में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक

मेला संयोजक विकास वीरानी ने बताया कि बिगत छह वर्षों से संचालित हो रहा यह मेला सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आयोजन का पारिवारिक संगम है। यहां भारतीय संस्कृति की झलक आंगतुकों को देखने को मिल रही है। मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए समिति द्वारा इस वर्ष और बेहतर प्रयास किए गए हैं। मेले में महामंत्री हरीश कुमार राम, वीरेंद्र तिवारी, दीपक बैरागी, दीपक शर्मा, सुनील वैष्णव, सुनील शाह, महेंद्र नामदेव, चन्दन वर्मा, अखिलेश नागर, शैलेंद्र सिंह जाट, विनय सिंह, केश कुमार शाह, मधु भवनानी, आफताब सिद्दीकी, देवेंद्र चौकसे, इंद्रजीत, नीलम चौकसे, सुनील वैष्णव, गोपाल शर्मा सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सहकारी समितियों ने किया किसानों के खातों में भुगतान

ग्वालियर में गोदामों तक नहीं पहुंचा 1.78 करोड़ का धान

ग्वालियर। सहकारी समितियों से जुड़े लोगों ने फिर बड़ा धान घोटाला कर दिया है। इस बार एक करोड़ 78 लाख रुपए की धान का भुगतान तो सरकार किसानों को कर चुकी है पर यह गोदामों तक नहीं पहुंचा है। मामला उजागर होने के बाद भी जिम्मेदार अफसर वसूली और कार्रवाई पर चुप्पी साधे हैं। चार दिन पहले भोपाल से आए अफसर इस मामले में सख्ती का निर्देश दे गए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में धान की खरीदी 29 नवंबर से 20 जनवरी 2022 के बीच हुई थी। ग्वालियर जिले में पिछले सीजन में 46 समितियों ने 1 लाख 23 हजार 329.39 मीट्रिक टन धान की खरीदी 1950 रुपए क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की। इसमें से 1 लाख 22 हजार 408.89 मीट्रिक टन धान तो गोदामों तक पहुंच गया है पर बाकी 920.50 मीट्रिक टन धान गोदाम तक पहुंचा ही नहीं। जबकि इसके भुगतान के तौर पर सरकार किसानों के खाते में 1.78 करोड़ डाल चुकी है।

19 समितियों में गड़बड़ी

मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारी आर टेंभरे ने गड़बड़ी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिन 46 समितियों ने धान खरीदी की है इनमें से 19 में ही गड़बड़ी लग रही है। उन्होंने कहा कि समितियों को कमीशन की राशि में से वसूली की जाएगी। अंचल के दतिया जिले में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है पर वहां पर मात्रा सिर्फ 60 क्विंटल है।

गड़बड़ी समिति स्तर पर हुई है, इसलिए वसूली भी उनसे ही की जाएगी। जरूरी होने पर समितियों की संपत्ति कुर्क करेंगे।
- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर ग्वालियर

शिवपुरी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने कहा

परजीवियों का प्रबंधन कर पशुपालक होंगे आत्मनिर्भर

शिवपुरी के 470 पशु पालकों को किया गया प्रशिक्षित

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

खेती के साथ ही भारत सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए पशुपालकों को योजनाओं के साथ ही वैज्ञानिक तकनीकी से भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसी क्रम में देशभर के साथ ही मध्यप्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को वैज्ञानिक तकनीकी मुहैया कराई जा रही है। अटारी जोन-9 के माध्यम से केंद्र सरकार के मछली, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा प्राप्त लक्ष्य के क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी में एक तीन दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण पशुओं में परजीवी नियंत्रण विषय पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह के मार्ग दर्शन एवं तकनीकी कौशल के साथ आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के पांच विकास खंडों के 26 गांवों के 66 पशुपालाकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर तकनीकी ज्ञान अर्जित किया गया।

परजीवी पहुंचाते हैं हानि

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पशुओं में परजीवी बहुत हानि पहुंचाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं जिसमें अंत: एवं वाह्य परजीवी प्रमुख हैं। पशुओं को परजीवियों से बचाने के लिए इलाज नहीं, बल्कि प्रबंधन की जरूरत होती है। परजीवियों के कारण पशुओं में बीमारियों का प्रकोप, गाय-भैंस के बच्चों की मृत्युदर में बढ़ोतरी, दुग्ध उत्पादन एंव शारीरिक विकास में गिरावट, बांझपन, टिक्स फीवर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसका उचित समय पर प्रबंधन कर इन समस्याओं पर पूर्णत: काबू पाया जा सकता है।

प्रबंधन करना बहुत आसान

पशुपालकों को यह समझना होगा कि पशुओं को अंत: परजीवियों की दवा समय-समय पर खिलाकर एवं वाह्य परजीवियों दवा शरीर पर लगाकर प्रबंधन करना बहुत आसान है। परजीवियों का प्रबंधन करके ही पशुपालन में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि केवीके शिवपुरी को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के अंतर्गत अटारी, जबलपुर के माध्यम से पांच दिवसीय प्रशिक्षणों एवं 200 पशुपालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था। जिसके तहत: उक्त प्रशिक्षण के अलावा पूर्व के माहों में चार प्रशिक्षण क्रमश: करैरा, बदरवास, नरवर और पोहरी विकास खंडों में आयोजित किए जा चुके हैं।

पशुपालकों को मुफ्त में दी दवाइयां

प्रशिक्षणों में पशुपालन से जुड़ीं 197 महिलाओं एवं 240 पुरुषों को मिलाकर 200 के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 437 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पशुपालकों के लिए क्रमश: बकरी पालन, डेयरी पशुओं का प्रजनन प्रबंधन, दुधारू गाय और भैंसों में दुग्ध उत्पादन के लिए संतुलित आहार का महत्व, कड़कनाथ मुर्गी पालन एवं पशुओं में पर जीवी प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षणों में पशुपालकों को वैज्ञानिक जानकारी के साथ ही उन्हे उनके पशुओं, बकरियों एवं मुर्गियों के लिए पेट के कीड़ों की दवा आदि भी नि:शुल्क प्रदान कराई गई है।

इनका रहा सहयोग | प्रशिक्षणों में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसएस कुशवाह, डॉ. एमके भार्गव, डॉ. जेसीगुप्ता, डॉ. पुष्पेंद्र सिंह, डॉ. एएल बसेडिया, एनके कुशवाह, विजय प्रताप सिंह कुशवाह, सतेन्द्रगुप्ता, आरती बंसल एवं नीतू वर्मा आदि का प्रशिक्षण एवं व्यवस्था में सहयोग रहा है।

देश में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 386 जिलों में पशुपालकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों का आयोजन कर हजारों पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया है। अटारी, जोन-9, जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा मप्र में 15 तथा छत्तीसगढ़ में 13 जिलों के पशुपालकों को प्रशिक्षणों से तकनीकी ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिला है, जिसे वह अपना कर लाभांवित हो सकेगें। तकनीकी ज्ञान से पशुपालक अपने पशुपालन को धंधा बना सकेगें।

-डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक, भाकृअप-अटारी, जोन-9, जबलपुर

नई कृषि मंडी के चालू होने से पहले बदला आदेश

अशोकनगर में 14 से नई धनिया की होगी नीलामी

अशोकनगर। संवाददाता

अशोक नगर की नवीन कृषि उपज मंडी चालू होने के आदेश में एक बार फिर संशोधन किया गया है। अब वहां पर केवल धनिया की नीलामी बोली लगाई जाएगी, जबकि अन्य जींस की नीलामी बोली कृषि उपज मंडी में ही होगी। वहां पर उपज की तुलाई करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से आदेश में बदलाव किया गया है। धनिया की नीलामी के बाद वहीं पर तुलाई भी की जाएगी। नवीन कृषि उपज मंडी के 14 मार्च से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन मंडी चालू होने से पहले ही विवादों में घिर गई और उसके आदेश में संशोधन करना पड़ गया। पहले सभी प्रकार के जींस की नीलामी बोली होनी थी, लेकिन वहां पर तौल की व्यवस्था नहीं होने के कारण भारतीय किसान संघ सहित सभी किसान नीलामी कराने को तैयार नहीं थे। इसी के चलते बैठक के दौरान और आदेश में संशोधन किया गया है। अब नवीन कृषि उपज मंडी 14 मार्च को शुरू तो होगी, लेकिन उसमें अन्य जींस की नीलामी को छोड़कर केवल धनिया की नीलामी की जाएगी। व्यापारियों को फड के लिए जगह दे दी गई है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)